श्री आई. के. गुजराल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के राज्य में जो हाउसिंग बोर्ड बना हुआ है उस की भी सहायता की जा रही है। अभी जयपुर की स्कीम में काफी रुपया मंजूर हुआ है। हाउसिंग बोर्ड्स जितने भी चल रहे हैं उन्हें सैंटर की तरफ से सहायता दी जा रही है लेकिन अधिकतर रुपया जो है वह रियासत अपने प्लान के बजट में से देती है। उस के अलावा उन्हें जमीन बेचने की भी सुविधा दे दी गई है ताकि उससे भी उनकी आमदनी हो।

Use of Soyabean as rich Protein Food

*307. SHRI NIHAR LASKAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Soyabean has the highest protein content; and

(b) if so, what steps are being/have been taken to popularise the use of this rich protein food ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) The average protein content in Soyabean is 40%.

(b) Steps taken include—

(1) A crash programme for expanding the cultivation of Soyabean has been taken up by the Department of Agriculture under which 4 lakh hectares have been planned to be brought under soyabean cultivation by 1973-74.

(2) Steps have been initiated for development of processing facilities for soyabean.

(3) Projects for undertaking research and development in regard to soyabean processing have also been formulated.

(4) Use of edible soyabean flour in children's food and other food preparation has been taken up.

SHRI NIHAR LASKAR : Because of the easy availability of soyabean in the country, may I know whether any attempt has been made to popularise this among our population because of the high protein content in it ?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : Government appreciate that soyabean has a very high protein content. It is a very important protein-rich food and therefore, necessary steps are being taken through agricultural universities and private parties. The Food Corporation itself is going to establish one big plant for processing of soyabean.

श्री भागीरथ भंवर : मंत्री महोदय ने यह बताया है कि सोयाबीन की खेती को देश में बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश के किस किस राज्य में सोयाबीन की खेती करने के लिए अधिक उपयोगी जमीन उपलब्ध है और जो काश्तकार सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं उनको सरकार द्वारा सबसिडी या अन्य प्रकार की कोई और सहायता दी जायगी ?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : At the moment government is considering how the incentive price for the farmer can be given. Maharashtra and Madhya Pradesh Governments are purchasing at Rs. 100 a quintal. A minimum statutory price for procurement is under the consideration of the Government of India. Price incentive will be given to them so that production is encouraged.

श्री नाथूराम अहिरवार : क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों में मध्य प्रदेश जो सोयाबीन की फसल उगाई गई उसे न तो सरकार की ओर से खरीदा गया और न ही और किसी पार्टी की तरफ से खरीदा गया। किसानों ने काफी श्रम और पैसा लगा कर जो

सोयाबीन की फसल उगाई लेकिन उस की खरीद न हो सकी तो उस की खेती के ह्रास को रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ? मार्केटिंग फेसिलिटी न होने से और उसे खरीदने वाले न होने से किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसे रोकने के वास्ते सरकार क्या करने जा रही है ?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : At the moment Madhya Pradesh and Maharashtra governments are purchasing what is available in the market at Rs. 100 per quintal.

MR. SPEAKER : Next question. Shri P. Venkatasubbaiah. Absent. Next question. Shri Ram Avtar Shastri.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार का सवाल है कि यहां हाउस में इसे पूछे जाने पर उतेजना पैदा होगी और फलस्वरूप हाउस में गड़ बड़ पैदा होगी। इस प्रकार के प्रश्न जो यहां पर पूछे जाते हैं और उन में आर. एस. एस. के नाम पर जो एसी वैसी बाते उठाई जायेगीं उनके परिणामस्वरुप हाउस में उतेजना पैदा होगी और गड़बड़ होगी। इससे आपके काम में रूकावट पैदा होगी। इस लिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार सवाल के यहां हाउस में पूछे जाने की ईजाजत न दी जाय।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय के इजाजत देने के बाद ही यह सवाल यहां पर आज पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आवर में प्वाएन्ट औफ आर्डर का कौन सा तुक है।

रिजनल कालेज आफ एजुकेशन, अजमेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकलापों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरों का प्रतिवेदन

*309. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजनल कालेज आफ एजुकेशन, अजमेर के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकलापों एवं उनमें कालेज के स्टाफ के कुछ सदस्यों द्वारा भाग लेने के सम्बन्ध में जांच करने का भार केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था;

(ख) क्या सी० बी० आई० ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार के पास प्रेषित कर दी है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): (a) and (b). The Ministry of Home Affairs have made some confidential enquiries which inhicate that a section of the staff and students are engaged in R.S.S. activities.

(c) Since the information has been obtained by the Ministry of Home Affairs from secret sources, it will not be in public interest to disclose the details.

(d) The Regional College of Education, Ajmer is not a Government College. It falls under the administrative control of National Council of Educational Research and Training.

श्री रामावतार शास्त्री अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पिछले सत्र में भी उठाया गया था और उस समय उप मन्त्री जी ने जवाब दिया था कि इसको सी. बी. आई. के हवाले किया गया है। अब मालुम हो रहा है कि यह मन्त्रालय द्वारा कुछ गुप्त जांच की गई है। क्या यह बात सच है कि वहां पर आर. एस. एस. के खिलाफ आवाज बुलन्द करने वाले जो प्राध्यापक थे उन को भी उसी कैटेगरी में ला करके उक्त कालिज से बहुत दूर दराज ट्रान्सफर कर